11 .60% की विकास दर से आगे बढ़ रहा मप्र

दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा-

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 27 मार्च. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मप्र सरकार ने वित्तीय संसाधनों के समुचित प्रबंधन से अच्छे परिणाम देने का मॉडल तैयार किया है. हम कम संसाधनों में भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं. आज हमारा मप्र देश में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले प्रदेश के रूप में पहचाना जा रहा है.

मध्यप्रदेश 11.60 प्रतिशत की विकास दर से तेजी से आगे बढ़ रहा है. राज्य सरकार के पास 106 प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए समानुपातिक आवंटन के लिए पर्याप्त धनराशि है. जनकल्याण के साथ हम प्रदेश के औद्योगिक और अधोसंरचनात्मक विकास के लिए भी सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय मीडिया समूह की एनुअल समिट को संबोधित कर रहे थे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास के लिए हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है. हमारी कृषि विकास दर भी पहले से बेहतर हुई है. हमने बीते दो साल में औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देकर जीआईएस और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर मप्र में निवेश के लिए एक नया माहौल तैयार किया है. उन्होंने कहा कि बीते दो साल में प्रदेश में करीब 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर आया है. यह हमारे अपने राज्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. लाड़ली बहना योजना में हमारी 1 करोड़ 25 लाख 27 हजार बहने हैं. इनके हित में हम हर महीने 1500-1500 रुपये खाते में डाल रहे हैं. किसानों को किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं. भारत सरकार के वित्तीय व्यवस्था के जो उच्चतम मापदंड है उसके दायरे में रहकर हम अपनी आय-व्यय को विनियमित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष अपने पद के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे: मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अपने पद के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं. उन्हें कितना बड़ा मौका मिला है, लेकिन उन्होंने इस पद की गरिमा का पतन कर दिया है. भारत-पाकिस्तान में स्ट्राइक हो रही है और अपोजिशन लीडर सेना का मनोबल गिरा रहे हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. वर्ष 1971 में बांग्लादेश के समय स्व.अटल बिहारी वाजपेई पूरी दृढ़ता से सरकार के साथ खड़े रहे. उन्होंने कहा था हम सेना के साथ हैं. जब राष्ट्रीय संकट हो तो देश के साथ रहना चाहिए, यह विपक्ष को सीखना चाहिए.

राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल और वायु हमेशा सीमाओं से परे होती है. हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मप्र को दो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाओं की सौगात दी है. यह परियोजना राज्यों के हित में है. इस राष्ट्रीय परियोजना की 90 प्रतिशत लागत राशि भारत सरकार दे रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मध्यप्रदेश तो नदियों का मायका है. यहां 250 से ज्यादा नदियां हैं. हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के 15 जिले सालों से पीने के पानी, उद्योग और सिंचाई के लिए भारी कष्ट में थे. माननीय अटल जी की सरकार के वक्त नदी जोड़ो योजना बनी थी लेकिन राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकार के साथ तालमेल न होने से इस विषय को लटकाए रखा.

प्रदेश में मौसम की दोहरी मार, तापमान 41 डिग्री पार

07 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

भोपाल, 27 मार्च. मध्य प्रदेश में मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है. एक तरफ गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा दिया है, वहीं दूसरी ओर मौसम अचानक बदल रहा है. शुक्रवार को मौसम विभाग ने ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. प्रदेश में इस सीजन पहली बार नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक है. इसके अलावा ग्वालियर में 38.6, भोपाल में 37.4, इंदौर में 37.2 और उज्जैन में 37.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. कई अन्य जिलों में पारा 37 से 39 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे दिन में तेज गर्मी का अहसास हो रहा है.

मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के कारण हो रहा है. प्रदेश के ऊपरी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में दो चक्रवाती सिस्टम बन रहे हैं. इनके संयुक्त प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ रही है और आंधी-बारिश का दौर बन रहा है.

प्रदेश के करीब 28 जिलों में 30 मार्च तक इस सिस्टम का असर दिख सकता है. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि यह बारिश आम लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर देगी, लेकिन किसानों के लिए चिंता का विषय बन सकती है. इससे पहले मार्च में आए दो दौर की बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं, पपीता और केले की फसलों को नुकसान पहुँचाया था.

एक नजर में

ईडी ने 12 .62 करोड़ की दो अचल संपत्ति जब्त की

भोपाल. ईडी ने मेसर्स एक्सेल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स मंजू गर्ग व ऋषभ गर्ग से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में पीएमएलए के तहत 12.62 करोड़ रुपए की दो अचल संपत्तियां जब्त की हैं. जब्त संपत्ति में एक कृषि भूमि और एक कमर्शियल प्लॉट शामिल है. सीबीआई और एसीबी ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ कथित 42 करोड़ रुपए के फ्रॉड मामले में एफआईआर दर्ज की थी. जांच में सामने आया कि कंपनी ने टाटा मोटर्स की डीलरशिप के लिए बैंक से क्रेडिट सुविधा ली, लेकिन कोलैटरल सिक्योरिटीज में गलत जानकारी दी और पहले से गिरवी रखी संपत्ति का विवरण छुपाया.

रिश्वत लेते सहायक उप निरीक्षक रंगे हाथों ट्रैप

खरगोन. लोकायुक्त संगठन ने खरगोन जिले के कसरावद थाना में पदस्थ कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक रविंद्र कुमार गुरु को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. लोकायुक्त पुलिस इंदौर के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के अनुसार ग्राम चंदावड़, तहसील भगवानपुरा निवासी श्यामलाल उपाध्याय (69) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके विरुद्ध कसरावद निवासी एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के निराकरण के एवज में आरोपी उनसे 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था. शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने के बाद को ट्रैप दल का गठन किया गया.

पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में राहत का निर्णय ऐतिहासिक

भोपाल, 27 मार्च. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने पश्चिम एशिया में जारी वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह निर्णय श्री मोदी के संकल्प और समर्पण को और प्रगाढ़ करता है और देशवासियों को यह विश्वास दिलाता है कि उनकी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी.

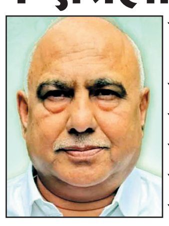

श्री खन्डेलवाल ने कहा कि इस निर्णय में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर, डीज़ल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर ड्यूटी लगाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व का प्रतीक है, जो देश की जनता को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने हर कठिन दौर में न केवल अपने पैरों पर खड़ा रहकर स्थिरता दिखाई है, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलकर नई ऊर्जा के साथ उभरा है.

प्रदेश में 2888 एलपीजी सिलेंडर जब्त

09 प्रकरणों में एफआईआर

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 27 मार्च. प्रदेश में एलपीजी , पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. भारत की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कच्चे तेल का भंडार भी पर्याप्त है. जिससे सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है.

फाइल फोटो

प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिये निरंतर कार्यवाही की जा रही है. अभी तक 2046 स्थानों पर जांच की गई और 2888 एलपीजी सिलेण्डर जब्त किये गए तथा 9 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि एलपीजी के बॉटलिंग प्लांटों में पर्याप्त स्टॉक है. ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्लांट अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं. प्रदेश में आज की स्थिति में सभी ऑयल कंपनियों के पास पेट्रोल/डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. सभी ऑयल कंपनियों के पास रोजाना नया स्टॉक पहुंच रहा है.

9 केएल पेट्रोल और 18 केएल डीजल की बिक्री

मप्र में सामान्य बिक्री प्रतिदिन लगभग 9 केएल पेट्रोल और 18 केएल डीजल की होती है. पिछले कुछ दिनों में ग्राहकों द्वारा पैनिक बाइंग करने से कुछ जिलों में बिक्री 2 से 2.5 गुना बढ़ गई है. इसी वजह से कुछ पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें और अस्थायी रूप से स्टॉक खत्म होने जैसी स्थिति बनी थी. पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एवं डीजल के स्टॉक की कमी की कोई स्थिति नहीं है. कंपनी के डिपो से भी डीजल/पेट्रोल की लगातार पूर्ति की जा रही है.

क्या मध्यप्रदेश में भी वैट घटाएगी सरकार

पेट्रोल पर 29 और डीजल पर 23 .22 % वैट ले रही सरकार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 27 मार्च. केंद्र सरकार ने डीजल-पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी है. इसी के साथ अब यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या मप्र सरकार भी डीजल- पेट्रोल पर लिये जाने वाले वैट में कटौती करेगी. मप्र देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हैं, जहां सबसे अधिक वैट लिया जाता है.

राज्य सरकार पेट्रोल पर 29 फीसदी वैट ले रही है, इसके अलावा 2.5 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स भी वसूल रही है, इतना ही नहीं एक प्रतिशत सेस भी लिया जा रहा है. इस तरह प्रदेश में 24 से 25 रुपए प्रति लीटर कुल टैक्स की वसूली हो रही है, वही स्थिति डीजल की भी बनी हुई है. डीजल पर भी राज्य सरकार 23.22 फीसदी वैट वसूल रही है. इसी तरह 1.5 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स के साथ ही एक फीसदी सेस भी ले रही है. इस तरह डीजल पर प्रति लीटर लगभग 16 से 18 रुपए तक सभी मिलाकर टैक्स की वसूली हो रही है. ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि जब केंद्र सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी है तो क्या सरकार भी केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए वैट में कमी करेगी या फिर अतिरिक्त टैक्स की वसूली या फिर सेस की वसूली बंद करेगी. डीजल, पेट्रोल को अभी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सका है.

अभी मप्र सहित सभी राज्य वैट लगा रहे हैं, इससे राज्य सरकार को ज्यादा आमदनी हो रही है. इसलिए राज्य इसे जीएसटी के दायरे में लाने का लगातार विरोध कर रहे हैं.

इजरायल-अमेरिका के साथ ईरान के युद्ध के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की सामान्य आवाजाही प्रभावित हुई है. हांलाकि भारत पर अब तक इसका असर नहीं पड़ा है और देश में दुनिया के कई दूसरे देशों से भी पेट्रोलियम, एलपीजी की आवक बढ़ा दी गई है, लेकिन अफवाहों के चलते प्रदेश के कुछ शहरों के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी है, वहीं एलपीजी के लिए भी लोगों में घबराहट की स्थिति बनी हुई है. इस कारण प्रदेश में डीजल, पेट्रोल की 25 फीसदी तक खपत बढ़ गई है.

पुलिस ने गुम मोबाइल फोन बरामद किए

977 गुम फोन वास्तविक मालिकों को लौटाए

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 मार्च. मध्यप्रदेश पुलिस के साइबर सेल ने विशेष अभियान के तहत 2 करोड़ 86 लाख रुपये मूल्य के 977 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया है.

बरामद मोबाइल फोन संबंधित व्यक्तियों को पुलिस कार्यालय बुलाकर विधिवत सौंपे गए, जिससे प्रदेशभर में लोगों ने पुलिस की सराहना की. राजगढ़ जिले में ऑपरेशन ट्रेस एंड रिटर्न के तहत उन्नत तकनीक और सीईआईआर पोर्टल का उपयोग करते हुए लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपये मूल्य के 451 मोबाइल फोन बरामद किए गए. ये मोबाइल फोन बिहार, राजस्थान, गुजरात और उत्तरप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से ट्रेस किए गए.

इंदौर में अपराध शाखा ने सिटीजन कॉप एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए करीब 60 लाख रुपये मूल्य के 251 मोबाइल फोन बरामद किए. इसी तरह नर्मदापुरम में 147 मोबाइल फोन (20 लाख रुपये से अधिक), रतलाम में 100 मोबाइल फोन (करीब 20 लाख रुपये) बरामद किए गए. सीधी में मिशन मिसिंग मोबाइल के तहत 20 मोबाइल लौटाए गए, जबकि बड़वानी में पुलिस ने एक आदतन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 8 मोबाइल फोन जब्त किए.

डायल 112 की तत्परता से बची 3 की जान

घायलों को समय पर पहुंचाया अस्पताल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 मार्च. मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-112 टीम ने तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए रतलाम जिले में मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल एक बच्ची सहित तीन लोगों को समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई.

यह घटना 26 मार्च को जावरा के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत बेगमपुरा चौराहे के पास सवेरा होटल के निकट हुई. राज्य स्तरीय डायल-112 कंट्रोल कक्ष, भोपाल को सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें पति-पत्नी और एक बच्ची घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही निकटतम डायल-112 वाहन को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंचकर आरक्षक संदीप कुमरे और चालक नंद लाल ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत वाहन की मदद से जावरा के शासकीय अस्पताल पहुंचाया. डायल-112 टीम की त्वरित कार्रवाई के कारण सभी घायलों को समय पर उपचार मिल सका. यह घटना दर्शाती है कि मध्यप्रदेश पुलिस आपात स्थिति में आमजन की सहायता के लिए सदैव सजग, संवेदनशील और प्रतिबद्ध है.

कार्यों में देरी, ठेकेदार पर 5 लाख की पेनल्टी

उज्जैन. जिले में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत चल रहे सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों में देरी पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए संबंधित ठेकेदार पर पांच लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है. संभाग आयुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने खजूवाली मस्जिद से केडी गेट तक सड़क चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कार्य की धीमी प्रगति और निर्माण में देरी पाए जाने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

वंदे भारत, शताब्दी में डीआरएम ने किया निरीक्षण

भोपाल, 27 मार्च. मंडल रेल प्रबंधक भोपाल पंकज त्यागी ने वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर सचित शर्मा और वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर आरपी खरे के साथ मंडल में सुरक्षा और यात्री सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया.

डीआरएम ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से झांसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में फुटप्लेट निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने लोको पायलट के साथ सुरक्षा मानकों का अवलोकन किया और यात्रियों से संवाद कर सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया. झांसी में रनिंग रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए क्रू को बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

श्रीधाम एक्सप्रेस अब एलएचबी रैक से चलेगी

भोपाल. रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए जबलपुर-निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन के रेक को आईसीएफ से एलएचबी कोच में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है. गाड़ी संख्या 12192 जबलपुर-निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 30 मई 2026 से जबलपुर से एलएचबी कोच में चलेगी, जबकि 12191 निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस 31 मई 2026 से निजामुद्दीन से एलएचबी रैक में संचालित होगी. नई एलएचबी कंपोजीशन में 01 वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, 02 वातानुकूलित द्वितीय, 05 वातानुकूलित तृतीय, 01 वातानुकूलित तृतीय इकॉनमी, 07 स्लीपर, 04 सामान्य, 1 एसएलआरडी और 1 जनरेटर कार सहित कुल 22 कोच होंगे.

वापसी यात्रा में डीआरएम ने शताब्दी एक्सप्रेस से रानी कमलापति स्टेशन तक पुन: फुटप्लेट निरीक्षण किया और परिचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया. डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुरक्षा, समयपालन और यात्री सुविधाओं के मानकों को और मजबूत किया जाए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण यात्रा अनुभव उपलब्ध कराया जा सके.

खिलाफत यह फैसला पहले से महंगाई से जूझ रही जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा : पटवारी

जीतू ने बिजली दर वृद्धि का किया विरोध

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 मार्च. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर 1 अप्रैल से प्रस्तावित 4.80 प्रतिशत बिजली दर वृद्धि का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला पहले से महंगाई से जूझ रही जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा.

पटवारी ने अपने पत्र में कहा कि जब खाद्य पदार्थ, ईंधन और शिक्षा जैसी आवश्यक चीजों की लागत लगातार बढ़ रही है, ऐसे समय में सरकार इस वृद्धि की आवश्यकता को स्पष्ट करने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक में 22 से 24 प्रतिशत तक हुई निरंतर वृद्धि का हिस्सा है. आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0 से 50 यूनिट की दर 3.65 रुपये से बढ़कर 4.45 रुपये प्रति यूनिट हो गई है, जो 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाती है. साथ ही, ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के नाम पर हर महीने 3 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त बोझ भी उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है. पटवारी ने बार-बार हो रही दर वृद्धि पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिजली कंपनियों के घाटे की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती और क्या कुप्रबंधन तथा कथित भ्रष्टाचार का भार आम जनता पर डाला जा रहा है.

उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग में दी जा रही छूट को भी सीमित लाभ वाला कदम बताते हुए इसे नीतिगत दिखावा करार दिया.

बिजली को मूलभूत आवश्यकता बताते हुए पटवारी ने दर वृद्धि को तत्काल वापस लेने, अतिरिक्त शुल्कों की पारदर्शी समीक्षा करने, बिजली कंपनियों के घाटे की स्वतंत्र जांच कराने और गरीब व मध्यम वर्ग के लिए राहत पैकेज घोषित करने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा.

कुणाल चौधरी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र किसानों को राहत देने की मांग

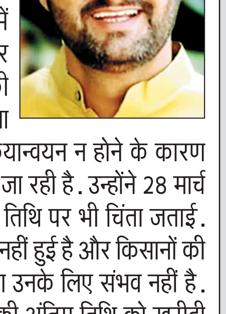

भोपाल. कांग्रेस सचिव एवं कालापीपल के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश के किसानों को राहत देने की मांग की है. चौधरी ने अपने पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश के किसान लगातार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. मौसम की अनियमितता, फसलों के उचित दाम नहीं मिलना और सरकारी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन न होने के कारण किसानों की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है. उन्होंने 28 मार्च को कृषि ऋण अदायगी की निर्धारित अंतिम तिथि पर भी चिंता जताई. चौधरी ने कहा कि अभी तक गेहूं खरीदी शुरू नहीं हुई है और किसानों की फसलें बिना बिके पड़ी हैं, ऐसे में ऋण चुकाना उनके लिए संभव नहीं है. उन्होंने सरकार से मांग की कि ऋण वसूली की अंतिम तिथि को खरीदी प्रक्रिया पूरी होने तक बढ़ाया जाए और 18 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज को माफ किया जाए. साथ ही, बिजली बिल वसूली में सख्ती के मामलों की निंदा करते हुए उन्होंने किसानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने तथा बिजली बिल माफी या व्यापक राहत पैकेज देने की मांग की.

वाराणसी में गूंजेगी सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा

भोपाल, 27 मार्च. मध्यप्रदेश सरकार की पहल पर गौरवमयी अभियान विक्रमोत्सव-2026 के अंतर्गत वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल तक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा. आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह सांस्कृतिक आयोजन उज्जैन से शुरू हुई श्रृंखला का विस्तार है, जो अब काशी तक पहुंच रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य भारतीय न्यायप्रियता, वीरता और सुशासन के प्रतीक हैं और यह मंचन जन-जन को उस गौरवशाली कालखंड से परिचित कराएगा.

कार्यालय नगर परिषद रामपुर बाघेलान जिला- सतना (म.प्र.)

Office No- 07672-271336 E-mail:-cmorampurbaghelan@mpurban.gov.in

क्रमांक / 659 / न.प. / ई- टेन्डर / 2026 — रामपुर बाघेलान दिनांक 27/03/26

द्वितीय ई- निविदा आमंत्रण सूचना (अल्पकालिक)

नगर परिषद रामपुर बाघेलान द्वारा बाजार बैठकी वसूली वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु ऑनलाईन निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से (दिनांक 05.04.2026 से 31.03.2027 कुल 361 दिवस हेतु) आमंत्रित की जाती है । इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय डाउनलोड करने एवं निविदा से संबधित समस्त शर्ते एवं जानकारी वेबसाइट http://www.mptenders.gov.in से एवं कार्यालय नगर परिषद रामपुर बाघेलान से प्राप्त की जा सकती है। निविदा मे किसी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जावेगा ।

क्र.	सिस्टम टेण्डर नं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि (361 दिवस हेतु)	धरोहर राशि (रू. में)	निविदा फार्म का शुल्क	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	2026_UAD_495091_1	बाजार बैठकी वसूली	8,43,838.00	30,000.00	1000.00	03.04.2026 समय 05.30 बजे तक

उक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 28.03.2026 समय 10.30 बजे से दिनांक 03.04.2026 समय 05.30 बजे तक बेवसाइट पर लागू प्रोसेसिंग शुल्क के ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य जानकारी कार्यालय में कार्यालयीन समय में एवं वेबसाईट http://wwwmptenders.gov.in पर से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी प्रकार के संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

शर्ते:-1. दरें केवल ऑनलाईन ही मान्य होगी। 2. निविदा की शर्तों की पूर्ति के आभाव में निविदा अमान्य होगी एवं बंधनयुक्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी । 3. विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास रहेगा ।

(रामसखी कचेर) अध्यक्ष, नगर परिषद रामपुर बाघेलान ,जिला सतना

(अरूण कुमार श्रीवास्तव) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद रामपुर बाघेलान ,जिला सतना (म.प्र.)